Control on population

*184. DR. ABRARAHMED:†
SHRI RAJEEV SHUKLA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state;

(a) whether Government have assessed the impact of various family planning measures adopted to control the population explosion in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to introduce new methods adopted in foreign countries In the field of family planning; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHATRUGHAN SINHA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The measures adpoted to control population by the Government have yielded favourable results, the Total Fertility Rate has come down from 6in 1951 to3.2 in 1999. The Birth Rate has come down from 40.8 in 1951 to 25.8 during the year 2000. as per the estimates of Sample Registration System (SRS), Registrar General of India. According to National Family Health Survey conducted in 1998-99, 42% ofthe couples with two children and about 58% of couples with 3 children have adopted terminal methods of contraception. The child population (0—6 yeai^) has come down from 18% in 1991 to 15% in 2001 census, showing decline in fertility rate.

Among the major States with more than 20 million population, the States of Kerala and Tamil Nadu have already achieved a replacement level of fertility of a TFR of 2.1, while the States of Andhra Pradesh, Gujarat. Karnataka, Maharashtra, Orissa, Punjab and West Bengal are having a TFR of 2.2 to 3.0 and are in the direction ofreplacement level of fertility. There are 4 States v/r. Assam, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Haryana which are having a TFR of 3.1 to 4.0, while the 4 States of Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand have recorded a TFR of 4.1 to 4.7 as per the SRS, 1999.

Regarding the acceptance of terminal methods, the percentage of couples with two children have high acceptance in Southern and Western regipns, being 60% in Tamil Nadu, 72% in^ndhra Pradesh, 50% in Maharashtra and 60% in

†The question was actually asked on the Hoor ofthe House by Dr. Abrar Ahmed.

Karanataka, while in Northern States, the acceptance is on the lower side in the States of U.P. (11%) and Bihar (18%), Similarly the percentage of couples with 3 children acceptance terminal methods ranges between 65% to 85% in Southern and Western States, while in Northern States of Uttar Pradesh. Bihar, the range is between 24% to 31% as per NFHS 1998-99.

The proportion of child population aged 0 to 6 years also follows a similar pattern. Tamil Nadu has the lowest child population of 1 1%and Bihar with the highest of 20% as per Census 2001.

As regards introduction of new methods of family planning in the current financial year, the Government has introduced an advanced version of Intra Uterine Device Cu.T 380 A, which remains effective for ten years. Emergency Contraceptive Piils, which is hormonal contraceptive that can be used to prevent pregnancy following an unprotected act of sexual intercourse within the past 72 hours, is also included in the programme.

In addition, research work is being carried out for injectible contraceptive CYCLOFEM. injection on male contraceptive (RISUG) and paneem as microbicidal and contraceptive.

डा0 अबरार अहमदः सभापति महोदय, यह बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का सवाल है और आज देश की आबादी एक अरब से अधिक हो गई है और जितनी भी देश की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, वह सारी समस्याएं इस देश की बढ़ी हुई आबादी से सम्बन्ध रखती है। बहुत सारे छोटे-छोटे देश थाईलैंड, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, बंगला देश आदि ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है।

श्री सभापति: सीधा प्रश्न पूछिए।

डा0 अबरार अहमदः मेरी पहली सप्लीमेंट्री के छोटे-छोटे दो हिस्से हैं वह ध्यान से सुन लें।

श्री सभापतिः एक ही सप्लीमेंट्री कर लीजिए।

डा0 अबरार अहमदः एक ही सप्लीमेंट्री है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जवाब में जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसके अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अब भी पोपूलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप प्रांतों के अन्दर आबादी कम करने के लिए और जनसंख्या बढ़ने से रोकने के लिए मोटिवेशन के क्या तरीके अपना रहे हैं या कौन सा एक्शन प्लान है? सभापति महोदय, जब आप राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो वहां पर नगरपालिका और पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए एक कानून बनाया गया था कि अगर उसके दो बच्चों से ज्यादा हों तो वह ऑटोमेटिकली डिसक्वालिफाई हो जाएगा। तो क्या पूरे देश के लिए भी सभी राजनीतिक दलों से बात करके ऐसा कोई कानून बनाने का विचार रखते हैं?

श्री सभापतिः आप तो यही जवाब दे दीजिए कि कानून बनाने का विचार है या नहीं।

श्री शत्रुध्न सिन्हाः फिलहाल तो हमारा कानून बनाने का कोई विचार नहीं है।

श्री सभापतिः कभी विचार किया है सरकार ने?

श्री शत्रुध्न सिन्हाः अभी विचार कर सकते हैं।

श्री सभापतिः अभी तक किया है क्या?

श्री शत्रुध्न सिन्हाः विचार नहीं किया है कानून बनाने का।

डा0 अबरार अहमदः सर, आप उन्हें डायरेक्शन दें कि विचार नहीं किया है तो विचार करें।

श्री सभापतिः मैं माननीय सदस्यों से इस प्रश्न पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज से दो वर्ष पहले जब स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था तो दोनों सदनों की ओर से यह निर्णय हुआ था कि इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाए, इस पर चर्चा की जाए और इस संबंध में कोई पूर्ण व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह व्यवस्था के संबंध में सदन को जानकारी दें और यदि सदन को जानकारी देने के लिए सदन की आवश्यकता हो तो मैं सदन की अनुमति लेकर एक दिन इस पर चर्चा कराना चाहूंगा।

डा0 अबरार अहमदः माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है।

श्री सभापतिः अब हो गया दूसरा सवाल। ज्यादा सप्लीमेंट्री करोगे तो परिवार नियोजन के विरोधी बन जाओगे।

डा0 अबरार अहमदः नहीं सर, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा पार्ट है।

श्री सभापतिः आपके कहने पर ही हाऊस में डिस्कशन का इतना बड़ा क्रेडिट आपको मिल रहा है, आप उसको खो रहे हैं।

श्री राजीव शुक्लः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानून की बात तो आपने कह दी कि चर्चा होगी और सरकार बाद में बताएगी और उनका उत्तर भी काफी विस्तार से है, निश्चित रुप से सरकार का रेस्पांस इससे पता चलता है। कृप्या यह बताएं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो क्या इसके प्रचार का सिर्फ 36 करोड़ बजट था?

श्री सभापतिः उस समय चर्चा कर लेंगे।

श्री राजीव शुक्लः उस समय हर जगह परिवार नियोजन का प्रचार नजर आता था तो वह तो सरकार अब करवा सकती है। आज उसका तीन सौ करोड़ का बजट है लेकिन कहीं इसका प्रचार नजर नहीं आता।

श्री सभापतिः ठीक है, उस समय विचार करेंगे।

श्री राजीव शुक्लः जवाब तो देने दीजिए।

श्री सभापतिः जवाब मैं दे रहा हूं।

Investment by companies in Uttar Pradesh

* 185. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of investment made in the public and private sector in the State of Uttar Pradesh during the last three years; and

(b) the details of projects on which private companies/multinational companies invested in the State during this period?

THE MTNISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Details of investment made in the public and private sector in the State of Uttar Pradesh in terms of Industrial Entrepreneurs' Memoranda implemented and Industrial Licences issued during the last three years are as follows:

(Rs. m Crore)

	2000			2001			2002 (Jan-Aug)		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total	Public	Private	Total
U.P. ALL	9	400 191	409	2	724	726	28	274 215	302
INDIA	6258		6449	1141	14719	15860	9565		9780

(b) Between January, 2000 and August, 2002, a total of 129 projects have reported implementation in Uttar Pradesh. State-wise data on FDI inflows are not centrally maintained. Out of these 129 projects, the major sectors of investment are—the Metallurgical Industry (16), Mechanical Industry (16), Textiles (15), Food Processing (10), Sugar (8), Telecommunication (8), Paper and Paper Products (7) and Leather (5).